सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दु:ख होता है।

–चाणक्य

RNI No. RAJHIN/2001/05699

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

www.hellosarkar.com

हैलो सरकार

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें

फोन: 0141-2202717

मो: 9214203182

वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-25 | अंक-260 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, रविवार 24 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

वित्तीय अनुशासन को लेकर राजस्थान सरकार सख्त

सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध, ई-व्हीकल्स और डिजिटल वर्किंग पर जोर

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। प्रदेश में वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय में कड़ा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव, वैभव गालरिया द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण परिपत्र के तहत सरकारी खर्चों में भारी कटौती करने, ई-व्हीकल्स को बढ़ावा देने और डिजिटल कार्यप्रणाली को अपनाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस नए आदेश के बाद अब राजकीय व्यय (सरकारी खर्च) पर होने वाली सभी विदेश यात्राओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारकेड में कम होंगी गाड़ियाँ, चरणबद्ध तरीके से चलेंगे ई-व्हीकल्स मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने कारकेड में वाहनों की संख्या सीमित किए जाने के बाद अब सभी मंत्रियों, निगमों और आयोगों के पदाधिकारियों को भी अपने कारकेड में केवल अत्यावश्यक न्यूनतम वाहनों का ही उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही, परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलावों की घोषणा की गई है-

प्रथम चरण में सिर्फ ई-व्हीकल – सभी सरकारी पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। पहले चरण में शहर के भीतर काम करने वाले अधिकारियों के लिए केवल ई-व्हीकल ही खरीदे जाएंगे।

संविदा वाहनों में प्राथमिकता – सरकारी कामकाज के लिए किराए (संविदा) पर लिए जाने वाले वाहनों में भी ई-व्हीकल को प्राथमिकता दी जाएगी।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर – प्रदेश में ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए संबंधित विभाग समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करेंगे और लंबित प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी दी जाएगी।

कार पूलिंग – एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी अपने सरकारी या निजी वाहनों में कार पूलिंग को प्राथमिकता देंगे।

सरकारी भवनों में ही होंगे कार्यक्रम, बैठकें होंगी ऑनलाइन

सरकारी आयोजनों और बैठकों में होने वाले फिजूलखर्च को रोकने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। अब सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और

स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह और कार्यक्रम अनिवार्य रूप से राजकीय भवनों में ही किए जाएंगे। इसके अलावा, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभाग की सभी बैठकें यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित की जाएं।

पेपरलेस काम और डिजिटल ट्रेनिंग पर रहेगा ज़ोर

कार्यालयों को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों के मध्य भौतिक पत्राचार (कागजी फाइलों) के स्थान पर ई-ऑफिस, ई-फाइल और राज-काज पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, भौतिक रूप से होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जगह ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए %द्बत्तद्ध्न कर्मयोगी पोर्टल% का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऊर्जा बचत और प्राकृतिक खेती के लिए विशेष दिशा-निर्देश

पी.एम. सूर्यघर योजना –ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता दें। साथ ही, सभी राजकीय भवनों में भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।

बिजली की बचत – दफ्तरों में बिजली उपकरणों का उपयोग मितव्ययता से करने और कार्यालय समय के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से बंद करने को कहा गया है।

कृषि क्षेत्र में सुधार– कृषि विभाग को प्राकृतिक, जैविक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, एग्री-स्टैक (द्दह्लद्ब-स्ह्लड्डष्म्) पंजीयन और गैर-कृषि कार्यों में यूरिया के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी, विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट

वित्त विभाग ने साफ किया है कि इन नियमों की कठोरता से पालना कराने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव और विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। स्वायत्तशाषी संस्थाओं, राजकीय उपक्रमों, बोर्ड और विश्वविद्यालयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। हालाँकि, परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बेहद जरूरी या अति आवश्यक प्रकरणों में, पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव मिलने पर वित्त विभाग द्वारा इन प्रतिबंधों में शिथिलता (छूट) दी जा सकेगी।

सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले के लिए रोके वाहनों में घुसी तेज रफ्तार बस, 6 घायल

जयपुर। जयपुर-सीकर हाईवे पर बड़पीपली के पास आयोजित कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले को निकालने के लिए शनिवार शाम को सनसिटी गेट के पास रोके गए वाहनों में तेज रफ्तार एक स्लीपर बस जा घुसी। हादसे में छह लोग घायल हो गए। अचानक हुए हादसे से पुलिस-प्रशासन सकते में आ गया। घटनास्थल पर लोगों में चीख-पुकार के साथ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटना के बाद सीकर हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। हालांकि मुख्यमंत्री दुर्घटना से कुछ समय पहले घटनास्थल से निकल गए थे। पुलिस ने बताया कि जांच में बस के ब्रेक फेल होना सामने आया है। बस अहमदाबाद से पर्यटकों को लेकर खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रही थी। जानकारी के अनुसार बड़पीपली बस स्टैंड के पास सनसिटी गार्डन में भाजपा जयपुर जिला शहर का दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर आयोजित था। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंचे थे।

आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त

शाम करीब 6ः15 बजे सीएम का काफिला कार्यक्रम से वापस जयपुर लौट रहा था। इस दौरान राजावास पुलिया के पास पुलिस ने कट से यू-टर्न करवाने के लिए

जयपुर से सीकर जाने वाले वाहनों को रोक रखा था। अनियंत्रित बस की गति इतनी तेज थी कि टक्कर से आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। कई गाड़ियां टक्कर से पिचक गईं। पीछे से टकराने के कारण एक कार का पिछला हिस्सा पिचकने से गेट नहीं खुल पाया। पुलिस ने लोगों की सहायता से सीट पर फंसे सवार लोगों को बाहर निकाला। अन्य गाड़ियों में घायल हुए लोगों को भी पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

लंबा जाम लग गया

वहीं दुर्घटना के दौरान राजमार्ग पर काफी लंबा जाम लग गया। काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान मौके पर मौजूद एडिशनल एसपी राजेश गुप्ता, हरमाड़ा थानाधिकारी उदय सिंह यादव सहित पुलिसकर्मियों ने मामले को संभाला और क्रेन मंगा कर सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को एक तरफ करवाकर यातायात को सुचारु करवाया। भीड़ में मौजूद लोगों में बस चालक के खिलाफ काफी गुस्सा दिखा। कई लोगों ने बस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिसकर्मियों ने मामला संभाल लिया। बस अहमदाबाद से पुष्कर होते हुए खाटूश्यामजी दर्शन करने जा रही थी।

मोबाइल सुरक्षा का अचूक हथियार बना संचार साथी पोर्टल

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (ष्ठशञ्ज) द्वारा संचालित संचार साथी पोर्टल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल चोरी, फर्जी सिम, साइबर फ्रॉड और संदिग्ध कॉल्स से बचाव के लिए इस पोर्टल और मोबाइल ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि वर्तमान डिजिटल दौर में साइबर ठग लगातार नई तकनीकों के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में संचार साथी पोर्टल नागरिकों को मोबाइल और सिम कार्ड से जुड़ी सुरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के रूप में भी उपलब्ध है।

खोया या चोरी हुआ मोबाइल तुरंत करें ब्लॉक

पोर्टल के Block Your Lost/Stolen Mobile Handset फीचर के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन के IMEI नंबर को

ब्लॉक कर सकता है। इससे फोन में किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। मोबाइल मिलने पर उसे दोबारा अनब्लॉक भी किया जा सकता है।

खरीदने से पहले जांचें मोबाइल असली है या नहीं

Know Your Mobile (KYM) मॉड्यूल के माध्यम से लोग नया या पुराना मोबाइल खरीदने से पहले उसका द्वस्श्वद्ब नंबर चेक कर यह पता लगा सकते हैं कि फोन ब्लैकलिस्टेड, डुप्लीकेट या चोरी का तो नहीं है।

आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं, तुरंत करें जांच

TAFCOP (Know Mobile Connections in Your Name) फीचर से कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि उसके आधार या नाम पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं। यदि कोई अनजान नंबर दिखाई देता है, तो उसकी रिपोर्ट कर उसे बंद कराया जा सकता है।

फर्जी कॉल और मैसेज की भी कर सकते हैं शिकायत

चक्षु (ष्ट्रद्मस्॥) पोर्टल के जरिए व्हाट्सएप, कॉल या एसएमएस पर आने वाले फर्जी नौकरी, लॉटरी, केवाईसी अपडेट या बैंक अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी के प्रयासों की रिपोर्ट की जा सकती है।

विदेशी कॉल्स पर भारतीय नंबर दिखे तो रहें सतर्क

एडीजी सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी अब कॉलर आईडी स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल कर विदेश से कॉल करते हुए भारतीय नंबर प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मामलों में "Report Incoming International Call With Indian Number" फीचर के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी साइबर धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें। साथ ही साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 एवं 9257510100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र

हैलो सरकार न्यूज, नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 19वें रोजगार मेले में अलग-अलग सरकारी विभागों और संगठनों में 51 हजार से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि भारत के युवा 'विकसित भारत' की ओर बढ़ रही यात्रा को गति देने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। 'रोजगार मेला' युवाओं को नए अवसर प्रदान कर सशक्त बनाने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।

'विकसित भारत' के अहम सारथी हैं हमारे युवा-मोदी

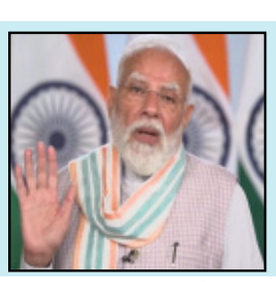

उन्होंने कहा, अभी दो दिन पहले मैं पांच देशों की यात्रा करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ पांच देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स से बातें हुईं, विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले और उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ ही साथ, मैं चाहता हूं कि देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।

उन्होंने कहा, आज स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ विनिर्माण से जुड़े क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी साझेदारी एक नई अर्थव्यवस्था के नए अवसर के दरवाजे खोल रही हैं। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ 'ग्रीन ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी' में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्री में मजबूत करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग-अलग क्षेत्र में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं।

31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश पर गर्माई सियायत

हैलो सरकार न्यूजजयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। जूली ने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताते हुए भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भागने का आरोप लगाया। जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार यह मुद्दा उठाती रही कि सरकार जान-बूझकर चुनाव टालना चाहती है क्योंकि उसे जनता के बीच जाने का डर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की लेकिन अदालत के फैसले ने सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनके अनुसार यह फैसला प्रदेश की जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले लगभग ढाई वर्षों से राज्य में विकास कार्य ठप पड़े हैं। कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जनकल्याणकारी

योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जनता को बताने के लिए उपलब्धियां नहीं हैं, इसलिए वह पंचायत और निकाय चुनावों से बचना चाहती थी। जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अब गांवों में जाकर जनता का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लोग सरकार की वास्तविकता समझ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों में संभावित हार के डर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक हर मंच पर भाजपा सरकार की मंशा का विरोध किया। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, जनआंदोलन और सार्वजनिक मंचों के जरिए कांग्रेस ने चुनाव टालने के प्रयासों को मुद्दा बनाया। जूली ने कहा कि अब कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता गांवों, ढाणियों और वार्डों में जाकर भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और पार्टी लोकतंत्र तथा जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

वस्तु परिवहन क्षेत्र के विरुद्ध वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राज्यव्यापी प्रवर्तन कार्रवाई

हैलो सरकार न्यूज] जयपुर। राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा शुक्रवार को देर रात तक राज्यभर में वस्तु परिवहन कंपनियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर एक साथ तलाशी एवं सर्वे कार्रवाई की गई। विभाग की तीनों प्रवर्तन शाखाओं तथा आठ क्षेत्रीय जोनों के संयुक्त समन्वय से संचालित इस अभियान में 33 परिवहन कंपनियों को शामिल किया गया। इन कार्रवाइयों के तहत परिवहन कंपनियों के कार्यालयों के साथ-साथ उनके संचालकों/प्रवर्तकों के आवासों पर भी कार्रवाई की गई।

यह अभियान अलवर, बीकानेर, चूरू, नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जयपुर एवं जोधपुर सहित कुल 10 जिलों में संचालित किया गया।

यह प्रवर्तन अभियान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की बड़े पैमाने पर हो रही चोरी का खुलासा करने एवं उसकी जांच के उद्देश्य से शुरू किया गया, जिसमें वस्तु परिवहन क्षेत्र की इकाइयों द्वारा अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग किया जा रहा था। दिनभर की कार्रवाई के दौरान प्राप्त अभिलेखों एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक कर चोरी 85 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है तथा जांच आगे बढ़ने के साथ यह राशि बढ़ने की संभावना है।

सामने आया कर चोरी का तरीका-

तलाशी कार्रवाई के दौरान वस्तु

परिवहन क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अपनाई जा रही अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। परिवहन कंपनियों द्वारा उन वस्तुओं पर भी 12 प्रतिशत जीएसटी दर्शाते हुए बिल जारी किए जा रहे थे, जिन पर वास्तविक कर दर शून्य है। इस प्रकार उत्पन्न किए गए अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग वास्तविक कर देनदारियों के भुगतान में नकद राशि के स्थान पर किया जा रहा था, जबकि कानून के अनुसार नकद भुगतान आवश्यक है।

इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार को मिलने वाला वैध जीएसटी राजस्व प्रभावित हुआ तथा कर चोरी को छिपाने के लिए फर्जी क्रेडिट श्रृंखला तैयार की गई।

पूरे परिवहन क्षेत्र की होगी जांच-विभाग द्वारा अब राज्यभर में संचालित अन्य वस्तु परिवहन ऑपरेटरों की भी चरणबद्ध जांच की जाएगी तथा कर चोरी के प्रत्येक मामले में आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की उन्नत डेटा विश्लेषण क्षमता के माध्यम से अब राजस्थान में संचालित प्रत्येक ट्रक एवं मालवाहक वाहन विभाग की निगरानी में है।

विभाग टोल प्लाजा रिकॉर्ड, ईंधन उपभोग डेटा, वाहन स्वामित्व अभिलेख तथा ई-वे बिल आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। वाहन स्वामियों को भी सचेत किया जाता है कि बिना वैध ई-वे बिल के माल परिवहन से संबंधित किसी भी कर चोरी के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा।

वंदे गंगा अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाएं -मुख्य सचिव

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर । प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 की तैयारियों एवं विभागवार गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे व्यापक जन आंदोलन के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जल संकट वाले जिलों में अभियान को गंभीरता एवं गति के साथ लागू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स से अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्यों एवं गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें तथा अभियान के प्रत्येक घटक की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन सहयोग से जुड़ा सामाजिक दायित्व है, जिसमें गांव स्तर तक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य सचिव ने रात्रि चौपालों की अवधारणा पर विशेष जोर देते हुए प्रभारी सचिवों एवं अधिकारियों को गांवों में रात्रि चौपाल आयोजित करने तथा प्रत्येक अधिकारी को प्रति माह कम से कम एक रात्रि गांव में प्रवास करने के लिए कहा। उन्होंने सभी प्रमुख शासन सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का दौरा कर अभियान गतिविधियों की समीक्षा करने तथा जमीनी स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन तथा जन जागरूकता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। विभागों को लागत दक्षता एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त एवं शासन

सचिव, पंचायती राज विभाग जोगा राम ने अभियान की रूपरेखा एवं विभागवार गतिविधियों की विस्तृत प्रस्तुति देते हुए बताया कि अभियान के दौरान राज्यभर में जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संरक्षण, पौधारोपण, श्रमदान, जनजागरूकता गतिविधियां, जल संरचनाओं का पुनर्जीवन तथा व्यापक जनभागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर तक गतिविधियों की मॉनिटरिंग मोबाइल एप एवं रियल टाइम रिपोर्टिंग व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 का आयोजन 25 मई से 5 जून तक किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 25 मई को जल संरक्षण संकल्प एवं जनजागरूकता गतिविधियों से शुरुआत होगी। 26 से 31 मई तक विभिन्न विभागों द्वारा जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संरक्षण, पौधारोपण, रैलियां, श्रमदान, स्कूल एवं ग्राम स्तर पर जनभागीदारी कार्यक्रम तथा जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान के तेहत 1 जून को जल संरक्षण विषयक प्रदर्शनी एवं तकनीकी गतिविधियां आयोजित होंगी, जबकि 2 से 5 जून तक राज्यभर में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं जनसहभागिता आधारित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का समापन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर व्यापक जनभागीदारी गतिविधियों के साथ किया जाएगा। बैठक में संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, प्रभारी सचिव एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़े।

धौलपुरशॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, पलभर में कई परिवारों का आशियाना जलकर राख

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। राजस्थान के धौलपुर से शनिवार को एक दुखद खबर सामने आई है, जहां शॉर्ट सर्किट से पलभर में भीषण आग लग गई और कुछ ही देर में कई परिवारों का सब जलकर स्वाहा हो गया। इस आगजनी में लोगों का अनाज सहित अन्य सभी कीमती सामान जलकर राख बन गया। शॉर्ट सर्किट की भनक लगते ही ग्रामीणों ने सबसे पहले विद्युत विभाग को सूचना देकर गांव की बिजली सप्लाई बंद करवाई, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। इसके बाद ग्रामीण भारी संख्या में मौके पर एकत्र हुए और पानी के टैंकरों, सबमर्सिबल पंपों व बाल्टियों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। हवा के तेज रुख के बावजूद ग्रामीणों की भारी मुस्तैदी से आग को पूरी बस्ती में फैलने से रोक लिया गया। इसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल से आग पर पूरी तरह काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब

कुछ जलकर राख हो चुका था।

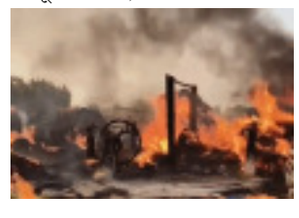

बताया गया कि आग से राजन सिंह पुत्र कतार सिंह, गंगा सिंह पुत्र भगवंत, मुन्ना पुत्र भगवंत जाट के 40 क्विंटल गेहूं, 120 क्विंटल भूसा, 2 झोंपड़ीनुमा घर, 400 फूंस के गट्ठर जिनसे झोंपडी बनाई जाती है, 100 किलो पानी की लेजम, 50 पाइप लाइन के पाइप, 5 चारपाई सहित घरेलू सामान सब कुछ पलों में राख हो गया। इस अग्निकांड में पीड़ित परिवारों की पूरी गृहस्थी, कीमती दस्तावेज, अनाज और पशुओं का चारा (भूसा) जलकर पूरी तरह राख हो गया। प्राथमिक आकलनों के अनुसार शॉर्ट सर्किट से हुए इस हादसे में पीड़ित परिवारों को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राजस्व टीम (पटवारी) भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ितों से बात कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी। वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग की है।

उपहारों की कूटनीति से वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष

(लेखक - विनोद कुमार सिंह तकियावाला)

विगत दिनों पाँच देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व को दिया भारतीय आत्मीयता, संस्कृति,सभ्यता व 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश

भारत केवल एक राष्ट्र नहीं,बल्कि हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, सभ्यता,दर्शन और मानवीय मूल्यों की जीवंत धारा है ।यहाँ राजनीति केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं रही,बल्कि समाज,संस्कृति और विश्व बंधुत्व की सम्पूर्ण चेतना से भी जुड़ी रही है ।भारतीय परंपरा ने सदैव दुनिया को यह संदेश दिया कि संबंध शक्ति से नहीं,संवेदना से स्थायी बनते हैं ।हमारी संस्कृति में अतिथि का स्वागत केवल औपचारिकता नहीं,बल्कि आत्मीयता और सम्मान का प्रतीक माना गया है ।वर्तमान दौर मे जब वैश्विक राजनीति लगातार बदल रही है,दुनिया आर्थिक प्रतिस्पर्धा, युद्ध,सामरिक तनाव और वैचारिक संघर्षों के दौर से गुजर रही है,तब भारत ﬁवसुधैव कुटुम्बकम्ﬂ की भावना के साथ विश्व मंच पर एक संतुलित और मानवीय शक्ति के रूप में उभर रहा है ।विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया पाँच देशों-संयुक्त अरब अमीरात,नीदरलैंड, स्वीडन,नॉर्वे और इटली-की यात्रा इसी बदलते भारत की नई तस्वीर बनकर सामने आई ।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की

यह यात्रा केवल राजनीतिक बैठकों, व्यापारिक समझौतों या रणनीतिक साझेदारियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय संस्कृति,लोक जीवन,कला,कृषि और सभ्यतागत मूल्यों की सुगंध को भी दुनिया तक पहुँचाने का माध्यम बनी ।मोदी ने इस पूरे दौरे के दौरान विदेशी नेताओं को जो सप्रेम भारतीय उपहार भेंट किए,वे केवल स्मृति- चिन्ह नहीं थे,बल्कि भारत की आत्मा,उसकी विविधता और उसकी सांस्कृतिक चेतना के जीवंत प्रतीक थे ।भारतीय कूटनीति का इतिहास सदैव सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा रहा है ।प्राचीन काल में जब भारत से व्यापारी समुद्री मार्गों से दक्षिण-पूर्व एशिया,अरब और यूरोप की ओर जाते थे,तब वे केवल वस्तुएँ ही नहीं ले जाते थे,बल्कि भारतीय संस्कृति,दर्शन,भाषा, संगीत,योग और जीवन शैली भी अपने साथ लेकर जाते थे ।यही कारण है कि आज भी इंडोनेशिया, थाईलैंड,कंबोडिया,वियतनाम और कई अन्य देशों की सांस्कृतिक परंपराओं में भारतीय सभ्यता की झलक दिखाई देती है ।मोदी ने इस सांस्कृतिक कूटनीति को एक नई दिशा दी है ।उन्होंने यह समझा कि दुनिया केवल आर्थिक शक्ति से प्रभावित नहीं होती,बल्कि सांस्कृतिक पहचान और मानवीय जुड़ाव भी देशों के बीच स्थायी संबंध बनाते हैं ।यही वजह है कि उनकी विदेश यात्राओं में भारतीय विरासत,परंपरा और सांस्कृतिक प्रतीकों की विशेष भूमिका दिखाई देती है ।इस पाँच देशों की यात्रा में सबसे अधिक चर्चा उन उपहारों की हुई, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेशी मेहमानों और नेताओं के लिए स्वयं भारत से लेकर गए ।सर्वविदित रहे कि इन उपहारों में भारत की पवित्र मिट्टी की खुशबू थी,अन्नदाता किसानों की मेहनत थी,बुनकरों की कला थी,लोक कलाकारों की कल्पना थी और भारतीय समाज की आत्मीयता थी ।संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को मोदी ने गुजरात का प्रसिद्ध केसर आम और मेघालय का अनानास भेंट किया ।सर्वविदित रहे कि भारतीय परंपरा में फल केवल स्वाद या उपभोग की वस्तु नहीं माने जाते,बल्कि समृद्धि,प्रेम और शुभकामनाओं के प्रतीक होते हैं। फलों का राजा आम का भारतीय साहित्य और लोक संस्कृति में विशेष स्थान रखता है ।संस्कृत साहित्य से लेकर हिंदी कविता तक आम को ऋतु,प्रेम और मधुरता का प्रतीक माना गया है ।भारतीय गाँवों में आम का पेड़ केवल फल देने वाला वृक्ष नहीं,बल्कि सामाजिक जीवन और पारिवारिक संस्कृति का हिस्सा होता है।

वही मेघालय का अनानास पूर्वोत्तर भारत की प्राकृतिक समृद्धि और जैव विविधता का प्रतीक है ।लंबे समय तक पूर्वोत्तर भारत राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में कम दिखाई देता था,किंतु प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति और विकास योजनाओं में पूर्वोत्तर को विशेष महत्व दिया है। उनके उपहारों में भी पूर्वोत्तर की झलक लगातार दिखाई देती है ।यह केवल प्रतीकात्मक नहीं,बल्कि यह संदेश भी है कि भारत की असली शक्ति उसकी विविधता में निहित है।

नीदरलैंड की महारानी को भारतीय लोककला से सुसज्जित हस्तनिर्मित उपहार भेंट किए गए ।भारतीय लोककलाएँ केवल रंगों और आकृतियों का संसार नहीं होती, बल्कि वे समाज की स्मृतियों, परंपराओं और सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति होती हैं। बिहार की मधुबनी,कलमकारी,पट्टचित्र, वारली और मिथिला जैसी लोककलाएँ भारतीय समाज की आत्मा को दर्शाती हैं ।इनमें गाँवों का जीवन,प्रकृति से जुड़ाव,स्त्री संवेदना और लोक संस्कृति की सहजता दिखाई देती है ।जब ऐसी कलाएँ विश्व नेताओं तक पहुँचती हैं, तो वे केवल सजावटी वस्तुएँ नहीं रहती,बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का दर्पण बन जाती हैं। यह भारत की 'सॉफ्ट पावर' का प्रभावी उदाहरण है। दुनिया के कई विकसित देशों ने अपनी सांस्कृतिक शक्ति को वैश्विक प्रभाव का माध्यम बनाया है ।स्वीडन के प्रधानमंत्री को मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक चाय भेंट की गई। यह केवल चाय नहीं,बल्कि पूर्वोत्तर भारत की प्रकृति,श्रम और सांस्कृतिक जीवन का प्रतीक है। लोकटक झील मणिपुर की पहचान मानी जाती है और उसके आसपास की संस्कृति भारत की जैव विविधता और पारंपरिक जीवन शैली का अद्भुत उदाहरण है ।भारतीय कूटनीति की यह खूबी रही है कि वह संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव को भी महत्व देती है ।दुनिया के कई देशों की राजनीति केवल हितों पर आधारित दिखाई देती है, लेकिन भारत ने हमेशा 'मानवता' को अपने वैश्विक दृष्टिकोण का केंद्र बनाया है ।यही कारण है कि भारत की विदेश नीति में 'विश्व बंधुत्व' और 'साझा विकास' जैसे विचार लगातार दिखाई देते हैं ।इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को असम का प्रसिद्ध मूंगा रेशम स्टोल भेंट किया गया ।मूंगा रेशम भारतीय बुनकरों की कला और परंपरा का अनुपम उदाहरण है ।असम के बुनकरों की मेहनत और कौशल इस रेशम में दिखाई देते हैं ।इसकी सुनहरी चमक केवल वस्त्र की सुंदरता नहीं,बल्कि भारतीय श्रम संस्कृति और लोकजीवन की गरिमा का प्रतीक है ।इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'मेलोडी' टॉफी भेंट करना कूटनीति के उस मानवीय और सहज पक्ष को सामने लाता है, जो संबंधों को औपचारिकता से ऊपर उठाकर आत्मीयता में बदल देता है। राजनीति और कूटनीति अक्सर गंभीर और औपचारिक दिखाई देती है,लेकिन भारतीय संस्कृति में हास्य,अपनापन और मानवीय गर्माहट को भी विशेष महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि यह छोटा-सा उपहार भी दुनिया भर के मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। मोदी की विदेश यात्राओं की एक विशेषता यह भी रही है कि वे भारत की क्षेत्रीय विविधता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते हैं ।कभी काशी की संस्कृति,कभी तमिल सभ्यता, कभी पूर्वोत्तर भारत की परंपराएँ और कभी राजस्थान या गुजरात की लोककलाएँ - हर क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास दिखाई देता है ।इससे यह संदेश जाता है कि भारत केवल महानगरों का देश नहीं,बल्कि गाँवों,लोक परंपराओं, किसानों,बुनकरों और कारीगरों की भी जीवंत सभ्यता है ।भारत की विदेश नीति में यह सांस्कृतिक आत्मविश्वास पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत हुआ है ।पहले वैश्विक मंचों पर भारत अक्सर विकासशील देशों की चुनौतियों तक सीमित दिखाई देता था,लेकिन अब भारत अपनी सभ्यतागत पहचान के साथ आत्मविश्वास से खड़ा दिखाई देता है। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ' वन अर्थ , वन फैमली वन फ्यूचर ' का संदेश इसी भारतीय दर्शन की आधुनिक अभिव्यक्ति था।

भारतीय संस्कृति का मूल भाव संघर्ष नहीं,सहअस्तित्व है ।यहाँ प्रकृति को भी पूजनीय माना गया, नदियों को माँ कहा गया,वृक्षों को जीवन का आधार माना गया और संपूर्ण विश्व को परिवार की दृष्टि से देखने की परंपरा विकसित हुई। यही कारण है कि भारत जब दुनिया से संवाद करता है, तो उसके पीछे केवल सामरिक या आर्थिक सोच नहीं होती, बल्कि मानवीय मूल्यों की भी भूमिका होती है ।मोदी की इस यात्रा के दौरान व्यापार,रक्षा, हरित ऊर्जा,तकनीकी सहयोग और निवेश से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण समझौते हुए ।यूरोप के देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध और मजबूत हुए ।खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाएँ बनीं ।इन सबके बीच भारतीय संस्कृति की उपस्थिति लगातार दिखाई देती रही।

दरअसल,किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता या आर्थिक प्रगति में नहीं होती, ,बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और सभ्यतागत आत्मविश्वास मे भी निहित होती है। जापान आज तकनीक के साथ अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है ।चीन अपनी सभ्यता और उत्पादन क्षमता दोनों का उपयोग करता है ।यूरोप अपनी विरासत को वैश्विक पहचान का हिस्सा बनाता है ।भारत भी अब अपनी सांस्कृतिक शक्ति को विश्व संबंधों का आधार बना रहा है ।भारतीय उपहारों में यह संदेश स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत आधुनिकता और परंपरा दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है ।एक ओर भारत डिजिटल तकनीक,अंतरिक्ष, रक्षा और आर्थिक विकास में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ भी दिखाई देता है ।यही संतुलन भारत को दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाता है।

नरेन्द्र मोदी की यह यात्रा इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय में भारत की विदेश नीति केवल राजनीतिक या आर्थिक दायरे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संस्कृति,सभ्यता,विरासत और लोकजीवन भी उसकी महत्वपूर्ण ताकत बनेंगे ।भारतीय हस्तशिल्प,वस्त्र,कृषि उत्पाद, पारंपरिक खान-पान और लोककलाएँ अब वैश्विक मंच पर भारत की नई पहचान बनती जा रही हैं ।यह केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं,बल्कि भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र और स्थानीय कारीगरों को वैश्विक पहचान देने का माध्यम भी है ।जब किसी विदेशी नेता को भारत का हस्तनिर्मित वस्त्र,लोककला या कृषि उत्पाद भेंट किया जाता है,तो उसके पीछे लाखों किसानों, बुनकरों और कारीगरों की मेहनत भी दुनिया तक पहुँचती है ।यह 'लोकल टू ग्लोबल' की उस सोच का हिस्सा है,जिसे भारत आज नई दिशा दे रहा है।

आज विश्व ऐसे दौर में खड़ी है जहाँ तकनीकी प्रगति तो तेज़ है,लेकिन मानवीय संवेदनाएँ कमजोर पड़ती दिखाई देती हैं ।ऐसे समय में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से दुनिया को संतुलन का संदेश दे रहा है ।भारतीय दर्शन सदैव यह कहता आया है कि विकास केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए,बल्कि उसमें मानवता, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए।

प्रधानमंत्री की पाँच देशों की यह यात्रा वस्तुतः उसी भारतीय दृष्टि का विस्तार थी ।भारतीय उपहारों के माध्यम से दुनिया ने महसूस किया कि भारत केवल उभरती हुई आर्थिक शक्ति नहीं,बल्कि एक ऐसी सभ्यता भी है,जो संबंधों में आत्मीयता,सम्मान और संवेदनशीलता को सबसे ऊपर रखती है ।जब भारत का केसर आम अरब की धरती तक पहुँचता है, मूंगा रेशम इटली के राजनयिक मंच पर दिखाई देता है,लोकटक चाय यूरोप की मेजों तक पहुँचती है और भारतीय लोककलाएँ विश्व नेताओं के हाथों तक जाती हैं,तब वास्तव में भारत अपनी संस्कृति के माध्यम से दुनिया के दिलों तक पहुँच रहा होता है ।निस्संदेह, प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की विदेश नीति के उस नए अध्याय का संकेत है, जहाँ कूटनीति केवल समझौतों और दस्तावेजों में नहीं,बल्कि संस्कृति, संवेदना,सभ्यता और ﬁवसुधैव कुटुम्बकम्ﬂ की आत्मीय भावना में भी लिखी जा रही है ।यही भारत की पहचान है,यही उसकी ताकत है और यही उसकी वैश्विक भूमिका का भविष्य भी।

संपादकीय

मां- बाप का हक

संवेदनाओं के क्षरण व आत्मकेंद्रित होती नई पीढ़ी के दौर में मां-बाप की बेकद्री विचलित करने वाली है। यह विडंबना ही है कि उन मां-बाप की देखभाल करने का निर्देश अदालत को देना पड़ रहा है, जिनका ऋण वे कभी चुका ही नहीं सकते। मां के रक्त से सींचे गए और पिता की पसीने से पले-बढ़े बेटे से यदि अदालत को कहना पड़े कि 'मां को घर में रहने के लिये एक कमरा, अलग बाथरूम और बुनियादी सुविधाएं दी जाएं', तो यह बात शर्मसार करने वाला है। जिस मां ने नौ माह तक बेटे को अपने पेट में पाला, उसे घर में रहने देने के लिये अदालत को निर्देश देना पड़े, इससे बड़ा कृतघ्नता का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। भले ही यह कोर्ट का आदेश हो, लेकिन यह एक अलिखित नैतिक दायित्व पहले से ही है। निश्चय ही यह घटनाक्रम हमारे समाज की बेहद कष्टदायक होती तसवीर को ही उकेरता है। सामान्य तौर पर मां-बाप अपना पेट काटकर, अपने सुख-सुविधाओं पर समझौता कर, बच्चों को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। एक मां-बाप ही होते हैं जो सच्चे मन से अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं। निस्संदेह, ऐसी पढ़ी-लिखी संतानों से अनपढ़ संतानें बेहतर हैं, जो कम से कम अपने वृद्ध माता-पिता के पास रहकर उनका ख्याल तो रखती हैं। यह सवाल परेशान करने वाला है कि जिस समाज में 'मातृ देवो भव' की सर्वस्वीकार्य मान्यता रही हो, वहां ये कैसी कलयुगी संतानें जन्म ले रही हैं? मां-बाप की बेकद्री की यह अकेली कहानी नहीं है, हर रोज अखबारों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें धन-संपत्ति के लिये मां-बाप से क्रूरता की जा रही होती है। निस्संदेह, यदि उनकी अवहेलना व उत्पीड़न का यह क्रम यूं ही चलता रहा तो बहुत संभव है भारत में भी पश्चिमी देशों जैस चलन शुरू हो जाएगा, जहां मां-बाप बच्चों को होश संभालने के बाद ही उन्हें पैरों पर खड़ा होने के लिये चलता कर देते हैं। दरअसल, पश्चिमी देशों में मां-बाप मानकर चलते हैं कि बड़े होकर बच्चों ने उनकी देखभाल नहीं करनी, अत- इनसे पहले ही किनारा कर लो। आधुनिकता व तरक्की की लाख इबारतें लिख ली जाएं, भारतीय समाज कभी पश्चिमी समाज की तर्ज पर नहीं चल सकता। भारत श्रवण कुमार का देश है और आज भी अधिसंख्य संतानें अपने मातृ-पितृ ऋण उतारती हैं। उनका ख्याल रखती हैं। विकृतियां महानगरीय संस्कृति की भी देन हैं। बच्चों की भी अपनी दुश्वारियां हैं। फिर भी भारतीय संस्कृति में वो शक्ति है जो पारिवारिक मूल्यों को सींचती है। बहरहाल, माता-पिता की सेवा-सम्मान व बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना महज एक सांस्कृतिक दिखावा नहीं है बल्कि संतानों का नैतिक-कानूनी दायित्व भी है। हाल ही में कोर्ट ने जिस घर में बेटे को वृद्ध मां को एक कमरा आदि देने को कहा, वह मकान वृद्धा के दिवंगत पति द्वारा ही बनाया गया था। जिसमें अपना हक पाने हेतु उसे न्यायिक हस्तक्षेप का सहारा लेना पड़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि किसी वृद्ध मां को आश्रय और आत्म स्वाभिमान हेतु बच्चों के खिलाफ कोर्ट-कचहरी करनी पड़े। निस्संदेह, यह उस भारतीय संयुक्त परिवार परंपरा का पराभव ही है जिसकी मिसाल पश्चिमी भोगवादी संस्कृति के अगुवा दिया करते थे। यहां न्यायालय के संवेदनशील व न्यायपूर्ण निर्णय की मुक्त कंठ से सराहना करनी होगी, जिसमें कोर्ट ने निर्णय के खिलाफ दी गई पुत्र की याचिका को खारिज कर जुर्माना लगाया। यह कष्टकारी ही है कि देशभर की अदालतें परित्यक्त-प्रताड़ित माता-पिता से जुड़े विवादों का सामना कर रही हैं। न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों ने दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को बेदखल करने तक के आदेश दिए हैं।

अलनीनो से प्रभावित होने के बाद भारत के पास क्या इंतजाम ?

(लेखक-सौरभ वार्ष्णेय)

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच अलनीनो एक बार फिर भारत के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रशांत महासागर के तापमान में असामान्य वृद्धि से उत्पन्न होने वाली यह मौसमी घटना भारतीय मानसून को सीधे प्रभावित करती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून की थोड़ी-सी गड़बड़ी भी खेती, अर्थव्यवस्था, जल संकट और महंगाई पर व्यापक असर डालती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि अलनीनो का प्रभाव गहराता है, तो भारत के पास इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम हैं? भारत का लगभग आधा कृषि क्षेत्र आज भी वर्षा पर निर्भर है। अलनीनो के कारण मानसून कमजोर पड़ता है, वर्षा कम होती है और कई राज्यों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसका सीधा असर किसानों की आय, खाद्यान्न उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही नहीं, बिजली उत्पादन, पेयजल आपूर्ति और उद्योग भी प्रभावित होते हैं। इसलिए अलनीनो केवल मौसम की समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारतीय मौसम विभाग अब पहले की तुलना में अधिक सटीक और समय रहते मौसम पूर्वानुमान जारी कर रहा है। उपग्रह तकनीक और आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के जरिए सरकार मानसून की स्थिति पर लगातार नजर रखती है। इससे राज्यों और किसानों को पहले से तैयारी करने में मदद मिलती है।

कृषि क्षेत्र में भी बदलाव की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार सूखा-रोधी बीजों को बढ़ावा दे रही है तथा किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई में सहारा देती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो सके।

जल संरक्षण की दिशा में भी कई प्रयास हो रहे हैं। जल शक्ति अभियान, तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और भूजल संरक्षण जैसे कार्यक्रमों पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। कई राज्यों ने स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सामुदायिक भागीदारी भी बढ़ाई है। यह समझना जरूरी है कि भविष्य में जल ही सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है।

ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत अब केवल जलविद्युत पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सूखे की स्थिति में जलाशयों का स्तर घटे, तब भी बिजली संकट को नियंत्रित किया जा सकेगा।

फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत पूरी तरह तैयार है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं सीमित हैं। जल संरक्षण योजनाएं कागजों से आगे नहीं बढ़ पातीं। किसानों तक समय पर सही जानकारी पहुंचाने में भी कई बार कमी दिखाई देती है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जलवायु परिवर्तन अब पहले से अधिक अनिश्चित और गंभीर होता जा रहा है। अलनीनो जैसी प्राकृतिक घटनाएं हमें यह संदेश देती हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए बिना भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। भारत को केवल राहत योजनाओं पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान देना होगा। जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती, हरित ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना समय की मांग है।

यदि केंद्र और राज्य सरकारें, वैज्ञानिक संस्थान, किसान और आम नागरिक मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, तो भारत अलनीनो जैसी चुनौतियों का मुकाबला मजबूती से कर सकता है। संकट बड़ा है, लेकिन तैयारी और सामूहिक प्रयास उससे भी बड़े हो सकते हैं।

अलनीनो से फसलों पर पड़ेगा प्रभाव ?

विश्व मौसम व्यवस्था में होने वाले बदलावों का सबसे अधिक असर कृषि पर पड़ता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून केवल मौसम नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। ऐसे में जब प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान बढ़ने से अलनीनो की स्थिति बनती है, तब उसका सीधा प्रभाव भारतीय मानसून और फसलों पर दिखाई देता है। यही कारण है कि अलनीनो को भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर चेतावनी माना जाता है। अलनीनो के दौरान सामान्यत- भारत में वर्षा कम होती है। मानसून कमजोर पड़ने से खेतों में पानी की कमी हो जाती है और खरीफ फसलें सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, दालें और गन्ना जैसी फसलें पर्याप्त वर्षा पर निर्भर रहती हैं। जब समय पर बारिश नहीं होती, तब बुआई में देरी होती है, उत्पादन घटता है और किसानों की लागत बढ़ जाती है। कई क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

धान की खेती पर अलनीनो का प्रभाव विशेष रूप से गंभीर माना जाता है। धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षा कम होने पर खेत सूखने लगते हैं और उत्पादन में भारी गिरावट आती है। इसी प्रकार दालों और तिलहन की फसलें भी कमजोर मानसून से प्रभावित होती हैं। पशुपालन पर भी इसका असर पड़ता है क्योंकि चारे की उपलब्धता कम हो जाती है ।अलनीनो केवल खेती तक सीमित समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब कृषि उत्पादन घटता है तो खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने लगती हैं। इससे महंगाई बढ़ती है और आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ता है। किसानों की आय घटने से ग्रामीण बाजारों की क्रय शक्ति भी कमजोर होती है ।ालांकि, वैज्ञानिक तकनीकों और सरकारी तैयारियों के माध्यम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत बनाना, सूखा-रोधी बीजों का उपयोग, जल संरक्षण, ड्रिप सिंचाई और फसल विविधीकरण जैसे उपाय किसानों को राहत दे सकते हैं। सरकार को समय रहते बीमा योजनाओं और राहत पैकेजों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए ताकि किसानों को नुकसान की भरपाई मिल सके ।भारत को अब पारंपरिक खेती के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के खतरों को ध्यान में रखकर कृषि नीति बनानी होगी। अलनीनो यह संकेत देता है कि प्रकृति के बदलते स्वरूप के सामने केवल मेहनत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और बेहतर प्रबंधन भी आवश्यक है। यदि समय रहते तैयारी की जाए तो इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है और देश की कृषि व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, कृषि जानकार, राजनीतिक विधि विचारक हैं।)

प्रतिभा और ज्ञान

एक संत को जंगल में एक नवजात शिशु मिला। वह उसे अपने घर ले आए। उन्होंने उसका नाम जीवक रखा। उन्होंने जीवक को अच्छी शिक्षा-दीक्षा प्रदान की। जब वह बड़ा हुआ तो उसने संत से पूछा, गुरुजी, मेरे माता-पिता कौन हैं? संत को जीवक के मुंह से यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन उन्होंने उसे सच बताने का निश्चय किया और बोले, पुत्र, तुम मुझे घने जंगलों में मिले थे। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे माता-पिता कौन हैं और कहां हैं? जीवक अत्यंत उदास होकर बोला, गुरुजी, अब आत्महीनता का भार लेकर मैं कहां जाऊं? इस पर संत उसे सांत्वना देते हुए बोले, पुत्र, इस बात से दुखी होने के बजाय तुम तक्षशिला जाओ और वहां विद्याध्ययन करके अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण समाज को आलोकित करो। जीवक अध्ययन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर वहां के आचार्य को उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया।

आचार्य ने उसकी स्पष्टवादिता से प्रभावित होकर उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश दे दिया। जीवक वहां पर कठोर परिश्रम के साथ विद्या प्राप्त करने लगा। वहां उसने आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की। संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन आचार्य जीवक से बोले, पुत्र, अब तुम मगध जाकर वहां के लोगों की सेवा करो। यह सुनकर जीवक परेशान हो गया। आचार्य उसे दुखी देखकर बोले, कौन सी बात तुम्हें टीस रही है? जीवक बोला, आचार्य, आप तो जानते ही हैं कि मेरा कोई कुल और गोत्र नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगा, लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। क्या आप मुझे अपने पास ही नहीं रख सकते? उसकी बात सुनकर आचार्य बोले, वत्स। तुम्हारी प्रतिभा और ज्ञान ही तुम्हारा कुल-गोत्र है। इन्हीं से तुम्हें सम्मान मिलेगा। आचार्य की बातों ने जीवक को नई दिशा दिखाई और वह मगध आ गया। वहां उसने लगन और मेहनत से काम किया। कुछ ही समय में वह पूरे मगध में आयुर्वेदाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

विचार मंथन

भय, लालच और पूंजीवाद के बीच महासंकट में फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था

(लेखक - सनत जैन)

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में जिस दिशा में आगे बढ़ी है, उसने विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिये बड़े गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। वर्ष 2014 के बाद देश में 'अच्छे दिन', हर साल दो करोड़ नौकरियां, विदेशों से काला धन वापस लाने और हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपये जैसे बड़े-बड़े वादों के सहारे आर्थिक समृद्धि का सपना दिखाया गया। 2026 तक आते-आते यह साफ दिखाई देने लगा है, इन वादों और वास्तविक आर्थिक स्थिति के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है। देश की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी मानी जाती है, लेकिन विडंबना यह है, कि वही युवा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी करोड़ों युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जहां नौकरियां मिलीं भी हैं, वहां ठेका व्यवस्था और कम वेतन ने युवाओं के शोषण को बढ़ावा दिया है। दूसरी ओर, सरकार भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का दावा करती रही। आर्थिक विकास का लाभ आम नागरिक तक अपेक्षित रूप में नहीं पहुंच पाया। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों को ऐतिहासिक आर्थिक सुधार बताया गया था, परंतु इनके दुष्परिणाम सबसे अधिक छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र और लघु-उद्योगों को झेलने पड़े। नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त करने का दावा किया गया, लेकिन अधिकांश नकदी फिर बैंकों में लौट आई। वहीं जीएसटी की जटिल व्यवस्था ने छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी। लाखों छोटे और मध्यम उद्योग बंद होते चले गए, जिससे रोजगार के अवसर भी घटते गए। इस बीच महंगाई लगातार बढ़ती रही। पेट्रोल-डीजल, खाद, बिजली, बैंकिंग सेवाएं और दैनिक जरूरतों की वस्तुएं महंगी होती गईं, जबकि आम लोगों की आय उस अनुपात में नहीं बढ़ी। परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग कर्ज के जाल में फंसता चला गया। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जैसे- मुफ्त राशन, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना या किसान सम्मान निधि का व्यापक प्रचार जरूर हुआ, लेकिन इनके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कई मामले सामने आए हैं। कई ऑडिट रिपोर्टों में करोड़ों रुपयों के फर्जी भुगतान और वित्तीय गड़बड़ियों को उजागर किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक और बड़ी चुनौती बढ़ता कर्ज और राजकोषीय घाटा है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बड़े पैमाने पर उधार लेकर विकास के दावे कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विकास टिकाऊ है? विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर भृष्टाचार हो रहा है। कमीशन की राशि 30 से 50 फीसद तक पंहुच गई है। इस कमीशनखोरी में कैसा विकास हुआ है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। जीडीपी की तुलना में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्याज के भुगतान में सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होने से भविष्य में आर्थिक संकट और गहरा होगा। इसके साथ ही, आर्थिक असमानता भी तेजी से बढ़ी है। एक ओर कुछ बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ी, वहीं दूसरी ओर आम नागरिक की बचत और क्रय-शक्ति कमजोर होती गई। ऑनलाइन व्यापार और वैश्विक कंपनियों के विस्तार ने स्थानीय कारोबारियों को भी प्रभावित किया है। छोटे दुकानदार और पारंपरिक व्यवसाय धीरे-धीरे बंद होते चले गये। रिटेल क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो गया। चिंता की बात यह भी है, भारत का आयात लगातार बढ़ रहा है, जबकि निर्यात अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाया। विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा है। वैश्विक हालात में पश्चिम एशिया का तनाव, तेल संकट और संभावित वैश्विक मंदी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। ऐसे समय में यदि आर्थिक नीतियां संतुलित और दूरदर्शी न हों, तो संकट और गहरा सकता है। यह भी सत्य है, सरकार के लिए चुनाव जीतना और लोकप्रिय घोषणाएं करना आसान होता है, सरकारों के लिए वास्तविक चुनौती देश की आर्थिक नींव को मजबूत बनाने की होती है। यदि बड़ी आबादी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, इससे सामाजिक असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। इतिहास गवाह है कि आर्थिक असमानता और बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहे, तो सामाजिक व्यवस्था पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकार को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार प्रचार आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर उत्पादन, रोजगार, कृषि, लघु-उद्योग और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान दे। युवाओं के लिए रोजगार, छोटे उद्योगों के लिए सरल कर व्यवस्था, मंहगाई और भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण समय की मांग है। सरकार के लिए आर्थिक नीतियों का आधार केवल टैक्स कलेक्शन नहीं, बल्कि आम नागरिकों का जीवन बेहतर हो, यह प्राथमिकता होना चाहिए।

सेबी ने कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन घर से काम की दी सलाह

बाजार नियामक ने सम्मेलनों और गैर-जरूरी यात्रा से बचने को भी कहा

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत की अपील के बाद बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऊर्जा संरक्षण और मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने अपने कर्मचारियों को अगले आठ हफ्तों के लिए हफ्ते में एक दिन घर से काम करने की सलाह दी है। यह कदम 25 मई से प्रभावी होगा। सेबी ने अपनी प्रशासनिक सलाह में कहा है कि ग्रेड ए से सी तक के अधिकारियों को रोटेशन के आधार पर यह सुविधा मिलेगी, जबकि ग्रेड डी और उससे ऊपर के अधिकारी, चेयरमैन/पूर्णकालिक सदस्यों के कार्यालयों में तैनात कर्मचारी तथा सेक्रेटेरियल कैडर के सभी कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय आएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समय ग्रेड ए से सी तक के कम से कम 50 प्रतिशत अधिकारी कार्यालय में मौजूद रहें। ऊर्जा बचाने के अन्य उपायों के तहत, सेबी ने विभागों को अगले आठ हफ्तों के लिए सम्मेलनों और विचार-मंथन कार्यक्रमों को टालने तथा गैर-जरूरी यात्रा से बचने का निर्देश दिया है। कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है, साथ ही हितधारकों के साथ वर्चुअल बैठकें करने की सलाह दी गई है। घर से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है, जिसकी आठ हफ्ते बाद समीक्षा की जाएगी।

एलआईसी की रणनीति का दिख रहा असर, नॉन-पार पॉलिसियों ने बढ़ाया वीएनबी

मजबूत चौथी तिमाही के प्रदर्शन के बाद बीमा कंपनी के शेयर में उछाल

नई दिल्ली ।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपनी पॉलिसी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है, जिसके तहत कंपनी अब ज्यादा सम-एश्योर्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग (नॉन-पार) पॉलिसियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस रणनीतिक बदलाव का सकारात्मक असर मार्च तिमाही के वित्तीय परिणामों में साफ दिखाई दिया है, जहाँ कंपनी के नए बिजनेस के मूल्य (वीएनबी) मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद, प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों ने एलआईसी के लिए अपने कमाई के अनुमान और कीमत लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा है और कंपनी के शेयर में भी तेजी देखी गई।

एलआईसी के रणनीतिक बदलाव ने मार्च तिमाही में उसके वित्तीय स्वास्थ्य को काफी मजबूती दी है। एमके ग्लोबल के अनुसार, चौथी तिमाही में एलआईसी का वीएनबी मार्जिन 25.7 प्रतिशत रहा, जो उनके 20.5 प्रतिशत के अनुमान से काफी अधिक था। इस मजबूत प्रदर्शन के बाद, ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए वीएनबी मार्जिन अनुमानों को 200-240 आधार अंक तक बढ़ाया है, जिससे इन वर्षों के लिए वीएनबी अनुमानों में 15-16 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है।

जेएम फाइनैंशियल ने वित्त वर्ष 2026 में मार्जिन में 360 आधार अंक की बढ़ोतरी का मुख्य श्रेय अनुकूल पॉलिसी मिश्रण को दिया है। प्रबंधन ने इस बात पर जोर दिया कि नॉन-पार सेगमेंट एलआईसी का सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय बना हुआ है, जिसने वित्त वर्ष 2026 में कुल वीएनबी में 53 प्रतिशत का योगदान दिया। जेएम फाइनैंशियल का अनुमान है कि व्यक्तिगत नॉन-पार बिजनेस के लिए मार्जिन 49 प्रतिशत, पार बिजनेस के लिए 12 प्रतिशत और ग्रुप बिजनेस के लिए 11 प्रतिशत रहेगा, जो कंपनी के व्यावसायिक मिश्रण की लाभदायकता को दर्शाता है। हालांकि, इक्विटी बाजारों में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट के कारण चौथी तिमाही में एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू (ईवी) में 6.2 प्रतिशत की कमी आई, जो 7.89 लाख करोड़ रुपये रही। यह सालाना आधार पर सिर्फ 1.6 प्रतिशत ज्यादा थी। एमके ग्लोबल ने बताया कि ईवी पर नकारात्मक आर्थिक बदलावों और परसिस्टेंसी व खर्चों से जुड़ी परिचालन धारणाओं में बदलावों का असर पड़ा। इसके बावजूद, जेएम फाइनैंशियल को उम्मीद है कि एलआईसी एम्बेडेड वैल्यू पर 11-12 प्रतिशत का परिचालन प्रतिफल देगी और वित्त वर्ष 2026-2028 के दौरान ईवी 14 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ेगी। शुक्रवार को एलआईसी का शेयर 1.58 प्रतिशत बढ़कर 813.35 रुपये पर बंद हुआ।

कच्चे कपास पर 11 फीसदी आयात शुल्क हटाएगी सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी राहत

नई दिल्ली।

कच्चे कपास की सभी किस्मों पर लागू 11 प्रतिशत आयात शुल्क को अस्थायी रूप से हटाने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक चार महीने की अवधि के लिए यह शुल्क हटाने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग को तत्काल राहत प्रदान करना है। हालांकि, इस कदम के संभावित प्रभावों को लेकर सरकारी मंत्रालयों और हितधारकों के बीच मंथन जारी है, जहाँ टेक्सटाइल क्षेत्र राहत की उम्मीद कर रहा है, वहीं किसानों के हितों की रक्षा को लेकर चिंताएं भी उठाई जा रही हैं। वस्त्र उद्योग लंबे समय से इस शुल्क को हटाने की वकालत कर रहा है। उनका कहना है कि घरेलू कपास की कम पैदावार और पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ी कीमतों के मद्देनजर यह कदम क्षेत्र को तत्काल राहत देगा और वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जैसे नेताओं ने भी नौकरियों के नुकसान और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री से इसे रद्द करने का आग्रह किया है। उद्योग का मानना है कि मौजूदा शुल्क उत्पादन लागत बढ़ाता है और सिंथेटिक फाइबर की ओर अनावश्यक झुकाव पैदा करता है, क्योंकि उस पर शुल्क छूट मिलती है। वहीं सरकार के कुछ अधिकारियों और कपास व्यापार से जुड़े वर्गों का तर्क है कि सीमित समय के लिए शुल्क हटाने से किसानों पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उनका यह भी कहना है कि निर्यातक एडवांस लाइसेंस स्कीम के तहत शून्य शुल्क पर आयात कर सकते हैं, इसलिए निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित होने का तर्क निराधार है। इन वर्गों को पिछली बार शुल्क हटाने के अनुभव से डॉलर के बहिर्वाह (1.1-1.2 अरब डॉलर) और खरीफ बुवाई से ठीक पहले किसानों के हितों को नुकसान पहुंचने का डर है, खासकर उन किसानों के लिए जिन्होंने बेहतर कीमतों की उम्मीद में लगभग 40 लाख गांठें रोक रखी हैं।

सुजलॉन एनर्जी को मिला एक और बड़ा ऑर्डर, रॉकेट बनेगा कंपनी का शेयर

मुंबई ।

विंड एनर्जी बनाने वाली भारत की प्रमुख कंपनी सुजलॉन एनर्जी को सनश्योर एनर्जी से 195 मेगावाट का एक नया और महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। यह एक 'रिपीट ऑर्डर' है, जो सुजलॉन के पिछले काम से सनश्योर एनर्जी की संतुष्टि को दिखाता है। इस नए ऑर्डर के साथ, सुजलॉन के खास 3 मेगावाट प्लेटफॉर्म वाले विंड टर्बाइनों की कुल बिक्री अब करीब 9 गीगावाट (गीगावाट) तक पहुंच गई है, जो कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह प्रोजेक्ट कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थापित होगा, जहां सुज़लॉन हवा से बिजली बनाने वाले 65 अत्याधुनिक टर्बाइन लगाएगी, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 3 मेगावाट है। कंपनी इन मशीनों की आपूर्ति के साथ-साथ उनके इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और उसके बाद के ऑपरेशन व मेंटेनेंस (ओक्यूएम) का पूरा जिम्मा भी संभालेगी। इस ऑर्डर के जुड़ने से अब कर्नाटक में सुज़लॉन के पास कुल मिलाकर 2 गीगावाट से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का काम आ चुका है, जो इस दक्षिणी राज्य में उसकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है।

दवा और आभूषण क्षेत्र को मिली आईपीओ की सौगात, सेबी ने दी मंजूरी

कोटेक हेल्थकेयर 295 करोड़ और दीपा ज्वेलर्स 250 करोड़ रुपये का नया निर्गम लाएगी

नई दिल्ली ।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दवा क्षेत्र की कोटेक हेल्थकेयर और आभूषण क्षेत्र की दीपा ज्वेलर्स को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की मंजूरी दे दी है, जिससे दोनों कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का रास्ता साफ हो गया है। इन कंपनियों ने पहले ही अपने मसौदा दस्तावेज (डीआरएचपी) सेबी के पास दाखिल किए थे और हाल ही में नियामक से आवश्यक टिप्पणियां प्राप्त कीं, जिसे आईपीओ लाने की अनुमति माना जाता है। कोटेक हेल्थकेयर का आईपीओ 295 करोड़ रुपये तक के नए शेयर निर्गम के साथ-साथ 60 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का प्रस्ताव है। कंपनी इस पूंजी का उपयोग नई परियोजनाएं स्थापित करने, मौजूदा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नए उत्पाद बनाने में करेगी, जिसके लिए 226.25 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। शेष राशि सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए खर्च होगी। वहीं दीपा ज्वेलर्स का आईपीओ 250 करोड़ रुपये के नए निर्गम और 1,18,48,340 शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। इस ओएफएस में प्रवर्तक अशोक अग्रवाल और सीमा अग्रवाल अपने शेयर बेचेंगे। यह मंजूरी इन कंपनियों को बाजार से पूंजी जुटाने और अपनी विस्तार योजनाओं को गति देने का अवसर प्रदान करेगी।

भारतीय शेयर बाजार में पूरे हफ्ते दिखा उतार-चढ़ाव का खेल

भारी बिकवाली के बीच भी दिखी खरीदारी की चमक, कुछ सेक्टरों ने दी संजीवनी

मुंबई ।

बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए अत्यधिक उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित झटकों से भरा रहा, जहां वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और घरेलू आर्थिक संकेतकों ने बाजार की चाल तय की। निवेशकों को हर दिन बाजार की शुरुआती गिरावट और फिर दिन के अंत में शानदार रिकवरी या इसके विपरीत शुरुआती तेजी के बाद सुस्त समापन जैसे नाटकीय परिवर्तन देखने को मिले। पश्चिमी एशिया में तनाव, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपये की रिकॉर्ड गिरावट और विदेशी फंड के प्रवाह जैसे कारकों ने बाजार की दिशा को लगातार प्रभावित किया, जिससे यह सप्ताह वैश्विक संकेतों और घरेलू लचीलेपन के बीच झूलता रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लाल निशान के साथ खुला, जहां सेंसेक्स 900 से अधिक अंक और निफ्टी 255 से अधिक अंक गिर गया। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 96.33 पर पहुंच गया, जिसने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी। हालांकि, बाजार ने दिन के अंत तक जबरदस्त वापसी करते हुए निवेशकों को चौंका दिया। सेंसेक्स मामूली रूप से 77.05 अंकों की वृद्धि दर्ज कर हरे निशान पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 6.45 अंकों की बढ़त रही। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर नियोजित सैन्य हमले रोकने और समझौते की संभावना जताने की खबर ने बाजार में एक नई उम्मीद जगाई। इस सकारात्मक खबर के दम पर भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी दर्ज की। सेंसेक्स 366.71 अंक उछलकर 75,706.88 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में भी 107.45 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। लेकिन यह तेजी भी दिन के अंत तक कायम नहीं रह पाई। शुरुआती बढ़त गंवाकर दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए, सेंसेक्स 75,200.85 और निफ्टी 23,618.00 पर कारोबार समाप्त हुआ। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर भारी बिकवाली के दबाव में खुले। बाजार विशेषज्ञों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, कमजोर होती मुद्रा और महंगाई की चिंताओं को निवेशकों की धारणा पर भारी पड़ने वाला बताया।

निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों में शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। हालांकि, प्रमुख एशियाई बाजारों में छाई सुस्ती और कमजोरी के बावजूद, भारतीय बाजारों ने जबरदस्त लचीलापन दिखाया। तेल व गैस, ऑटो और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में हुई जोरदार खरीदारी के दम पर घरेलू सूचकांकों ने दिन के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी की और अंततः हरे निशान में बंद होने में सफल रहा। सेंसेक्स 117.54 अंकों की बढ़त के साथ 75,318.39 और निफ्टी 41 अंकों की बढ़त के साथ 23,659 पर बंद हुआ। गुरुवार की स्थिरता और शुक्रवार का सकारात्मक समापन गुरुवार को पश्चिम एशिया संघर्ष के जल्द समाप्त होने की उम्मीदों के बीच तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक बाजारों में आई तेजी के कारण बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों में शुरुआती तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अच्छी बढ़त के साथ कारोबार शुरू किया। हालांकि, दिन का अंत बेहद सुस्त माहौल में हुआ। पूरे दिन के उतार-चढ़ाव के बाद दोनों प्रमुख सूचकांक लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए, सेंसेक्स 135.03 अंक टूटकर 75,183.36 पर और निफ्टी महज 4.30 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 23,654.70 पर सेटल हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को ईरान तनाव में नरमी की उम्मीद और वैश्विक आशावाद के चलते भारतीय बाजारों में तेजी जारी रही। प्रमुख एशियाई सूचकांकों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम पर बिना रिस्क हर महीने 10,000 पाएं

बाजार जोखिम से मुक्त, 7.4 फीसदी सालाना ब्याज दर के साथ

नई दिल्ली।

अगर आप भी एक गारंटीड और सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, जो नियमित मासिक आय दे सके, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (पीओएमआईएस) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यह स्कीम विशेष रूप से रिटायर लोगों और बाजार के जोखिम से मुक्त आय चाहने वालों के लिए बेहद लोकप्रिय है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है जो अपने निवेश पर नियमित मासिक आय चाहते हैं। यह स्कीम बाजार के उतार-चढ़ाव से पूरी तरह अप्रभावित रहती है, जिससे आपका मूलधन सुरक्षित रहता है और आपको तय ब्याज दर पर आय मिलती है। वर्तमान में पीओएमआईएस पर 7.4 फीसदी वार्षिक ब्याज दर मिल रही है, जिसका भुगतान हर महीने सीधे आपके खाते में किया जाता है। इस योजना में निवेश की सीमा निर्धारित की गई है। आप एकल खाते में अधिकतम 9 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, जबकि संयुक्त खाते में यह सीमा बढ़कर 15 लाख रुपये हो जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आपके कई एमआईएस खाते हैं, तब भी सभी खातों में कुल जमा राशि निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप एक संयुक्त खाते के माध्यम से

अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो मौजूदा 7.4 फीसदी ब्याज दर के अनुसार आपको हर महीने लगभग 9,250 रुपये की नियमित आय प्राप्त होगी। इस तरह, 5 साल में आप ब्याज के रूप में कुल करीब 5,55,000 रुपये कमा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। यह स्कीम उन लोगों के लिए आदर्श है जो रिटायरमेंट के बाद या किसी अन्य कारण से अपनी आय का एक स्थायी स्रोत सुनिश्चित करना चाहते हैं।

चुनौतियों के बावजूद चमकेगा पूंजीगत वस्तु उद्योग क्रिसिल

नई दिल्ली।

रेटिंग फर्म क्रिसिल रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग चालू वित्त वर्ष में 12-14 प्रतिशत की मजबूत दर से बढ़ेगा। फर्म के अनुसार सरकारी पूंजीगत व्यय और विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते विस्तार से इस वृद्धि को गति मिलेगी। क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली, खनन, तेल और गैस, धातु और वाहन जैसे क्षेत्रों में क्षमता का लगातार विस्तार पूंजीगत सामान की मांग को बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त, देश में डेटा सेंटरों के निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के बुनियादी ढांचे के विकास जैसे उभरते क्षेत्र भी इस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्रिसिल ने पिछले वित्त वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूंजीगत सामान उद्योग के लिए 12-14 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि को पक्का बताया है, जो इसकी मजबूती का संकेत है।

एसबीआई की बैंकिंग सेवाएं 25-26 मई को सामान्य रहेंगी

नई दिल्ली ।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के कर्मचारियों की 25 और 26 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को टाल दिया गया है। बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में हुई सकारात्मक बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। इससे एसबीआई के 52 करोड़ ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है और अब बैंक की सभी शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी। अखिल भारतीय एसबीआई कर्मचारी मासंघ (एआईएसबीआईएसएफ) ने पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती, आउटसोर्सिंग रोकने, करियर प्रगति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति में सुधार सहित 16 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर यह हड़ताल बुलाई थी। महासंघ के महासचिव एल चंद्रशेखर ने बताया कि प्रबंधन के साथ मुंबई में हुई बैठक काफी सकारात्मक रही, जिसमें उनकी कई प्रमुख मांगों पर प्रगति हुई है। इस फैसले से करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हड़ताल होने पर चौथा शनिवार, रविवार और ईद अल-अजहा की छुट्टी के कारण लगातार पांच दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होतीं। बैंक ने पुष्टि की है कि 25 और 26 मई को सभी बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक समेत 2 अन्य संस्थानों पर लगाया लाखों का जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने कृषि ऋण शुल्क, केवाईसी अपलोडिंग और निदेशक नियुक्ति से संबंधित निर्देशों के पालन में कमी पाई

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक निर्देशों का पालन न करने पर तीन वित्तीय संस्थाओं, सिटी यूनियन बैंक, मिंटिफी फिनसर्व और नेवा इन्वेस्टमेंट्स पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वित्तीय प्रणाली में अनुशासन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आरबीआई के एक बयान के अनुसार, सिटी यूनियन बैंक पर 10.10 लाख रुपये का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने 25,000 रुपये तक के कुछ कृषि ऋणों पर अनावश्यक रूप से ऋण-संबंधी शुल्क लगाए थे और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से जुड़े डेटा को क्रेडिट सूचना कंपनियों को प्रस्तुत नहीं किया था। मिंटिफी फिनसर्व पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने कुछ ग्राहकों के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) रिकॉर्ड को निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड नहीं किया था। इसके अतिरिक्त नेवा इन्वेस्टमेंट्स को 2.70 लाख रुपये का मौद्रिक दंड दिया गया। कंपनी ने निदेशकों की नियुक्ति करते समय आरबीआई से पूर्व लिखित अनुमति नहीं ली थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों में परिवर्तन शामिल था। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माने केवल संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए लगाए गए हैं।

आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरित किया

यह पिछले साल के लाभांश से 7 फीसदी अधिक

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया है।

यह राशि पिछले साल के 2.69 लाख करोड़ रुपए के लाभांश से लगभग 7 प्रतिशत अधिक है।

केंद्रीय बैंक ने हालांकि आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को बैलेंस शीट के 7.5 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया है, पर उच्च जोखिम प्रावधानों के कारण अर्थशास्त्रियों ने इस हस्तांतरण को बाजार की उम्मीदों से थोड़ा कम बताया है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने अपनी 623वीं बैठक में यह निर्णय लिया। इस रिकॉर्ड हस्तांतरण का एक प्रमुख कारण विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री से आरबीआई की आय में वृद्धि है। वित्त वर्ष 2026 में आरबीआई की बैलेंस शीट 20.61 प्रतिशत बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई, जिससे सकल आय में 26.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए सीआरबी में 1.09 लाख करोड़ रुपए का बड़ा हस्तांतरण करने का भी निर्णय लिया, जो पिछले वित्त वर्ष के 44,861.70 करोड़ रुपए से काफी अधिक है।

संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) सीआरबी को बैलेंस शीट के 4.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के बीच बनाए रखने का लचीलापन प्रदान करता है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सीआरबी अनुपात में कमी के बावजूद, उच्च प्रावधान आवश्यकताओं के कारण अधिशेष बाजार की उम्मीदों से थोड़ा कम रहा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक अर्थशास्त्री ने कहा `` कि आरबीआई का अधिशेष हस्तांतरण बाजार अनुमान से इसलिए कम रहा क्योंकि प्रावधान उम्मीद से अधिक रहा।

विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च सब्सिडी और कम कर संग्रह के कारण सरकार की राजकोषीय स्थिति पर दबाव बना रह सकता है।

उर्वरक और ईंधन सब्सिडी की उच्च आवश्यकता और कम कर संग्रह तथा तेल कंपनियों से कम लाभांश के कारण राजकोषीय दबाव बना रह सकता है।

हालांकि, इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के एक अर्थशास्त्री ने कहा कि यह उच्च हस्तांतरण भू-राजनीतिक स्थिति के कारण राजकोषीय घाटे पर कुछ दबाव कम करेगा।

आभूषण बिक्री पर दोहरी मार, राजस्व बढ़ेगा पर मांग घटेगी

चालू वित्त वर्ष में बिक्री मात्रा 13-15 फीसदी घटने का अनुमान

नई दिल्ली।

सोने की बढ़ती कीमतों और हालिया आयात शुल्क वृद्धि का असर देश के संगठित स्वर्ण आभूषण खुदरा क्षेत्र पर साफ दिख रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में आभूषणों की बिक्री मात्रा के लिहाज से 13 से 15 प्रतिशत तक घट सकती है। हालांकि, सोने की ऊंची कीमतों के चलते प्रति यूनिट अधिक मूल्य मिलने से इस क्षेत्र का कुल राजस्व 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।

इसके बावजूद, कंपनियों पर कार्यशील पूंजी और इन्वेंट्री लागत का दबाव बना रहेगा, हालांकि बेहतर नकदी प्रवाह से उनकी वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले वित्त वर्ष 24 में भी सोने के आभूषणों की बिक्री में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। भारत ने वित्त वर्ष 2024 में लगभग 720 टन सोने का आयात किया, जिससे लगभग 72 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई। व्यापार घाटा नियंत्रित करने और रुपए को सहारा देने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में सोने पर सीमा शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। क्रिसिल के अनुसार, पिछले वर्ष वैश्विक अनिश्चितताओं और रुपये में कमजोरी के कारण घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका सीधा असर उपभोक्ता मांग पर पड़ा है।

उपभोक्ता अब हल्के वजन और कम कैरेट वाले आभूषणों की ओर अधिक रुख कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में निवेश के रूप में सोने की मांग तेजी से बढ़ी है, जहां सोने की छड़ और सिक्कों की बिक्री 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, जबकि आभूषणों की मांग में करीब 25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आयात शुल्क में वृद्धि सोने की मांग पर बड़ा दबाव डाल सकती है और चालू वित्त वर्ष में कुल आभूषण बिक्री घटकर 620 से 640 टन तक रह सकती है, जो पिछले एक दशक का निचला स्तर होगा।

तुर्की-पाकिस्तान की धुरी को भारत का करारा जवाबः साइप्रस के साथ रणनीतिक साझेदारी

नई दिल्ली।

भारत ने पूर्वी भूमध्य सागर के महत्वपूर्ण देश साइप्रस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब तुर्की लगातार भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के बीच हुई बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिन्हें तुर्की के लिए जैसे को तैसा जवाब माना जा रहा है। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए पाँच साल का रोडमैप जारी किया है, जिसमें साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त, समुद्री परिवहन, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने का फैसला हुआ।

इस मौके पर आतंकवाद-रोधी उपायों पर संयुक्त कार्य समूह के गठन, राजनयिक प्रशिक्षण, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, खोज और बचाव कार्यों में समन्वय, तथा उच्च शिक्षा, अनुसंधान व सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित कुल छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की और साइप्रस के बीच समुद्री सीमाओं के निर्धारण, विशाल प्राकृतिक गैस भंडारों पर अधिकार और द्वीप के ऐतिहासिक राजनीतिक विभाजन को लेकर गहरा तनाव रहा है। साइप्रस गणराज्य अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून समझौते (यूएनसीएलओएस) के तहत करता है, जबकि तुर्की, जिसने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, साइप्रस की गैस खोज को अवैध मानता है। तुर्की अपनी ब्लू होमलैंड नीति के तहत भूमध्य सागर के बड़े हिस्से पर अपना कानूनी और सैन्य वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है।

साइप्रस भले ही एक छोटा देश हो, लेकिन उसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यह इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) के प्रस्तावित रास्ते पर पड़ता है और पूर्वी भूमध्य सागर में गैस की खोज में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। तुर्की के दक्षिण में सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने 1974 में कब्ज़ा किया था, जिससे

यह द्वीप दो हिस्सों में बंटा हुआ है। भारत का यह कदम तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन को उसी की भाषा में जवाब देने की रणनीति का हिस्सा है, जो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं और पिछले साल पाकिस्तान को सैन्य मदद भी दे चुके हैं। भारत अब साइप्रस की साइबर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने, उसकी छोटी नौसेना को मज़बूत करने और विभिन्न हिंद-प्रशांत मंचों के दरवाजे उसके लिए खोलने में मदद करेगा।

संसद सुरक्षा चूक मामले में यूएपीए के तहत 13 हजार पन्नों की चौथी चार्जशीट दाखिल

आरोपियों ने जानबूझकर संसद की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की साजिश रची

नई दिल्ली।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिसंबर 2023 के संसद सुरक्षा चूक मामले में बड़ी कार्रवाई कर अदालत में 13 हजार पन्नों की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दाखिल की गई है, जो मामले की गंभीरता को रेखांकित करती है। इस विस्तृत चार्जशीट में आरोपियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, दंगा भड़काने की साजिश रचना और देश की सुरक्षा को खतरे में डालना प्रमुख हैं। पुलिस ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने जानबूझकर संसद की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य देशभर में भय और अशांति का माहौल बनाना था। स्पेशल सेल ने अपनी जांच के दौरान जुटाए गए ठोस सबूतों, डिजिटल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया चैट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट तैयार की है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ यूएपीए की कई गंभीर धाराएं भी लगी हैं, जिसमें सरकारी कामकाज में बाधा डालना, ड्यूटी पर तैनात लोकसेवकों को रोकना, दंगा भड़काने के लिए उकसाना, सबूत मिटाना और आपराधिक साजिश रचना जैसे अपराध शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि

संसद जैसी संवेदनशील जगह पर हुई यह घटना महज एक प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक संगठित साजिश और व्यापक तैयारी के प्रमाण मिले हैं। जांच एजेंसियां अब इस मामले से जुड़े संभावित अन्य नेटवर्क, फंडिंग के स्रोतों और किसी भी विदेशी संपर्क की गहन जांच कर रही हैं।

गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, कुछ युवकों ने विजिटर्स गैलरी से लोकसभा सदन के अंदर कूदकर स्मोक कैनिस्टर छोड़े थे, जिससे देश भर में संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

डीजल संकट से प्रभावित होने लगी सफाई व्यवस्था

नई दिल्ली।

तेल कंपनियों की नई सप्लाई व्यवस्था का असर अब देश के अनेक स्थानीय निकायों की सफाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। कंपनियों ने पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि बल्क उपभोक्ताओं को अब डिस्काउंट रेट पर नहीं बल्कि निर्धारित बल्क रेट पर ही डीजल-पेट्रोल दिया जाए।

दरअसल मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है जहां भोपाल नगर निगम की कचरा कलेक्शन गाड़ियां जब डीजल लेने पहुंचीं तो पंप संचालकों ने पुराने रेट पर ईंधन देने से इनकार कर दिया। कर्मचारियों को बताया गया कि अब डीजल 142 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा, जबकि अब तक निगम को करीब 93 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल मिल रहा था। यह मामला जब नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा तक पहुंचा, तो उन्होंने इसका हल निकालने की सलाह दी। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद तेल कंपनियों ने कुछ दिनों तक पुराने रेट पर सप्लाई जारी रखने पर सहमति जताई है।

ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला वाहन के ईंधन से जुड़ा हुआ है और इस तरह से अन्य समस्याएं भी विभिन्न राज्यों के स्थानीय निकायों के सामने आ सकती हैं। इससे अनेक शहरों की सफाई व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ सकता है।

जहां तक मध्य प्रदेश की राजधानी का सवाल है तो नगर निगम भोपाल की करीब 1400 डीजल गाड़ियां प्रतिदिन लगभग 17 हजार लीटर डीजल की खपत करती हैं। नई दरें लागू होने पर निगम पर हर महीने करीब 2.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। जानकारी अनुसार डीजल सप्लाई में देरी के कारण करीब 2 से 3 घंटे तक कचरा कलेक्शन का काम भी प्रभावित रहा। कई इलाकों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण देर से हुआ, जबकि कुछ स्थानों पर गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच सकीं।

क्रूजर और ट्रक की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत

कलाबुरागी में भीषण सड़क हादसा

पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी

कलाबुरागी ।

कर्नाटक के कलाबुरागी जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसे में कम से कम पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना जिले के लादलापुर के पास हुई, जहां एक क्रूजर वाहन और ट्रक (लॉरी) के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही कलाबुरागी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ए. श्रीनिवासुलु ने तुरंत दुर्घटनास्थल का दौरा किया और घटना के कारणों को समझने के लिए मौके का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और टक्कर की असल वजह जानने के लिए मामले की जांच

क्रूजर और ट्रक की जोरदार टक्कर: 5 लोगों की दर्दनाक मौत

जारी है। सड़क हादसों का ऐसा ही एक और दर्दनाक वाकया पिछले महीने कर्नाटक के यादगीर क्षेत्र में भी सामने आया था। वहां एक कार और बस की आमने-सामने की भिड़ंत में सात लोगों की जान चली गई थी, जबकि दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कार में सवार सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे और वे रायचूर जिले के सिरवार तालुक के रहने वाले थे। यादगीर के एसपी पृथ्वीक शंकर ने बताया था कि यह हादसा सुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तभी वह सामने से आ रही बस से टकरा गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

सीएम मान बोले-आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे

चंडीगढ़ ।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपने पुराने रुख को बदलते हुए यूटर्न ले लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पंजाब सरकार अक्षरशः पालन करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य में आवारा कुत्तों के सफाई का अभियान शुरू करने की बात कही थी, जिसकी काफी आलोचना हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने अदालती निर्देशों के अनुरूप कदम उठाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए अपनी सरकार की नीति साफ की। उन्होंने लिखा कि अदालत के निर्देशों के अनुसार, सभी भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा ताकि बच्चे, बुजुर्ग और आम परिवार बिना किसी डर के घूम सकें। इसके साथ ही सरकार कुत्तों के लिए पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल (शेल्टर होम) बनाएगी और उनका सही तरीके से रखरखाव करेगी ताकि वहां उनकी उचित देखभाल की जा सके।मुख्यमंत्री ने आक्रामक कुत्तों से निपटने की योजना पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो कुत्ते पागल हैं, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं या अत्यधिक आक्रामक और खतरनाक हो चुके हैं और इंसानों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, उनके मामले में कानून के दायरे में रहते हुए दया-मृत्यु जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी कार्रवाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) नियमों के प्रावधानों के तहत ही

की जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में मानव जीवन के खतरे को कम करने के लिए पागल, लाइलाज बीमार और आक्रामक कुत्तों को दया-मृत्यु देने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने अपनी व्यवस्था में साफ कहा कि जब इंसानों की सुरक्षा और जान की तुलना जानवरों के कल्याण से की जाती है, तो संवैधानिक संतुलन निश्चित रूप से मानव जीवन के संरक्षण और सुरक्षा के पक्ष में ही झुकेगा।

पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ, एनआईए की चार्जशीट में खुलासा

लाहौर के कसूर में रहने वाला साजिद जट्ट आतंकियों का मेन हैंडलर था, भेजी थी लोकेशन

नई दिल्ली।

कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। यह खुलासा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की चार्जशीट में हुआ है। हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा आतंकी सैफुल्लाह उर्फ सैफुल्लाह साजिद जट्ट उर्फ लंगड़ा था। साजिद पाकिस्तान के लाहौर के कसूर में रहता है। साजिद जट्ट ही आतंकियों का मेन हैंडलर था। हमले में उसने तीनों आतंकियों से लगातार संपर्क बनाए रखा। वह उन्हें रियल टाइम डायरेक्शन दे रहा था। उसने ही हमले वाली जगह बैसरन वैली की लोकेशन भेजी थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान भी वह लगातार आतंकियों से बात कर रहा था। 15 दिसंबर 2025 को दाखिल चार्जशीट की डिटेल्स अब सामने आई हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमले में 26 बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी। इसमें एक स्थानीय युवक आतंकी से भिड़ गया और उसको आतंकियों ने गोली मार दी थी। इसमें 16 लोग घायल हुए थे।

एनआई चार्जशीट के मुताबिक टूरिस्ट गाइड परवेज अहमद जोठार और बशीर अहमद जोठार वक्त रहते जानकारी देते तो हमला को टाला जा सकता था। दोनों गाइड ने आतंकियों को बैसरन में देखा था लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को नहीं बताया। दोनों गाइड्स गिरफ्तार हो चुके हैं। हमले से एक दिन पहले तीनों आतंकियों ने गाइड परवेज की झोपड़ी में मदद मांग कर खाना खाया। जाते वक्त रोटी-सब्जी भी साथ ले गए थे। तीनों आतंकियों ने फायरिंग से पहले बैसरन घाटी में एक पेड़ के नीचे खाना खाया। वारदात के बाद तीनों ने धार्मिक नारे लगाते हुए हर्ष फायरिंग भी की थी।

चार्जशीट के मुताबिक यह हमला धर्म के आधार पर टारगेटेड मर्डर का है, जिसमें 25 टूरिस्ट और एक स्थानीय युवक की मौत हुई थी। 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीन पाकिस्तानी आतंकियों को भी आरोपी बनाया है।

साजिद 2005 में वह बॉर्डर क्रॉस करके दक्षिण कश्मीर के

कुलगाम में घुसा था। पैर में गोली लगने के कारण साजिद नकली पैर लगाता है। इसलिए उसे लंगड़ा कहा जाता है। उस पर भर्ती, फंडिंग, घुसपैठ और आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी लंगड़ा और उसके तीनों गुर्गे 20 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर की जेड मोड़ टनल फायरिंग में भी शामिल थे। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी।

पंजाब के 9 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट

60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, चंडीगढ़ में स्कूल बंद

चंडीगढ़।

पंजाब में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में बारिश, तेज आंधी और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पटियाला, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, मानसा, मालेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर और रूपनगर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं चंडीगढ़ सहित नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा में हीटवेव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 28 मई तक गर्म हवाएं चलने की चेतावनी दी है। शुक्रवार को मौसम में बदलाव और हिमाचल व सीमावर्ती इलाकों में हुई बारिश के कारण तापमान में 3.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद बठिंडा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

30 जून तक स्कूल बंद

भीषण गर्मी को देखते हुए पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के समय में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने 30 जून तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है।

सेंट्रल बैंक की 8 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 2380 करोड़ की बोली

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 8 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) प्रक्रिया शुरू की है। इस हिस्सेदारी बिक्री के जरिए सरकार को करीब 2,380 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार निवेशकों ने पहले दिन इस इश्यू को अच्छा प्रतिसाद दिया और बोली निर्धारित हिस्से से कई गुना अधिक पहुंच गई। इस बिक्री के बाद भी सरकार की बैंक में हिस्सेदारी 81 प्रतिशत से अधिक बनी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेशकों की बढ़ती रुचि और बैंकिंग सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन के कारण इस ओएफएस को अच्छा समर्थन मिला है।

कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर ठगी, पुलिस ने दी चेतावनी

लुधियाना ।

पंजाब में इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नाम पर एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है। ठग डिजिटल संगठन के नाम पर लोगों को वॉट्सएप पर लिंक भेजकर शिकार बना रहे हैं, इसके बाद लुधियाना पुलिस ने जनता को जागरूक करने के लिए वीडियो जारी कर चेतावनी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जालसाज युवाओं को लुभाने के लिए आकर्षक संदेश भेज रहे हैं, जिसमें देश की पुकारू सिस्टम बदलने का समय आ गया है और युवाओं के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसी बातें लिखी होती हैं। इन संदेशों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने की अपील कर एक लिंक दिया जाता है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह लिंक असल में एक फिशिंग लिंक है। जैसे ही कोई व्यक्ति भावनाओं में बहकर या उत्सुकतावश इस लिंक पर क्लिक करता है, उसका मोबाइल फोन तुरंत हैक होता है। फोन हैक होते ही पीड़ित के फोन में मौजूद सभी बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड और निजी डेटा सीधा ठगों के पास पहुंच जाता है। इस डेटा का इस्तेमाल करके अपराधी न केवल बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लेते हैं, बल्कि पीड़ित के नाम पर लाखों रुपये का कर्ज भी ले सकते हैं। लुधियाना पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और जज्बाती होकर तुरंत कोई फैसला न लें। डिजिटल साक्षरता और सतर्कता ही इस तरह की ठगी से बचने का एकमात्र तरीका है।

हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, हजारों श्रद्धालुओं ने लगाए बोले सो निहाल के जयकारे

चमौली।

उत्तराखंड के चमौली जिले में मौजूद सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार सुबह 11:30 बजे हजारों श्रद्धालुओं के लिए पूरे विधि-विधान के साथ खोल दिए गए। कपाट खुलने के इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश-विदेश से 3000 से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंचे थे। जैसे ही द्वार खुले, पूरी लोकपाल घाटी बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठी। इस मौके पर गुरुद्वारा को भव्य रूप से सजाया गया था, जिसमें करीब 5 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल हुआ। धार्मिक अनुष्ठानों के तहत, सचखंड से गुरुग्रंथ साहिब को दरबार में विराजमान किया गया, जिसके बाद शबद कीर्तन, अरदास और सुखमनी साहिब का पाठ पूरा हुआ। गुरुद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने इन अनुष्ठानों की जानकारी दी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था पंच प्यारों के नेतृत्व में बेस कैंप घांघरिया से 15,225 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। गोविंदघाट से शुरू होने वाली 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को पारकर ये श्रद्धालु यहां पहुंचे, जहां अभी भी कई फीट बर्फ जमी हुई है। भारतीय सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद भारी बर्फ हटाकर पैदल मार्ग को सुचारु बनाने में अहम भूमिका अदा की। कपाट खुलने के साथ ही भ्यूंडार घाटी का गुरु आस्था पथ फिर श्रद्धालुओं की चहल-पहल से गुलजार हो गया है। गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट ने अत्यधिक ऊंचाई और ठंड को देखकर श्रद्धालुओं से यात्रा मार्ग पर अनुशासन बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन करने की अपील की है।

अफ्रीकी देशों से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग

इबोला वायरस को लेकर सरकार अलर्ट, अराइवल टर्मिनल पर लगाए बैरियर

नई दिल्ली।

इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सख्त निर्देशों के बाद इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा और जांच के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत अब अफ्रीकन देशों से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। कोई भी यात्री बिना जांच के बाहर न निकल सके, इसके लिए एयरपोर्ट के अराइवल टर्मिनल पर विशेष बैरियर लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खतरे से निपटने और तैयारियों की समीक्षा के लिए एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता में एक हाईलेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सीआईएसएफ, ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन, कस्टम विभाग, सभी एयरलाइंस और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जांच में जिन यात्रियों में इबोला वायरस के लक्षण या ज्यादा खतरा दिखाई देगा, उन्हें सामान्य यात्रियों से अलग रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ऐसे संदिग्ध मरीजों को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट से बाहर निकालने और सीधे अस्पताल पहुंचाने के लिए एक अलग रास्ता तय किया गया है। इसके साथ ही हवाई सफर करने वालों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी की जा रही है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717